बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 169 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 04 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

लापरवाही से वाहन चलाया तो इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजे देने के लिए जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाते हुए मारा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसके परिजनों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मृतक के परिजनों की 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए विशेष याचिका खारिज की जाती है। 18 जून 2014 को एनएस रविश मल्लासांद्रा गांव से अरसीकेरे शहर जा रहा था।

वीकेंड में झमाझम बरसेंगे बादल: दिल्ली-एनसीआर में इस दिन से मिलेगी उमस से राहत; जानें आपके राज्य में कब होगी बरसात

नई दिल्ली।

देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले छह से सात दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इस अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, सिक्किम और झारखंड में अत्यधिक बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। जबकि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस अवधि में पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि मानसून के मौसम में पूर्वोत्तर का क्षेत्र सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस सप्ताह भारी बारिश का दौर इस क्षेत्र में आने की संभावना है। वीकेंड में पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि झारखंड और आसपास के क्षेत्रों पर बना निम्न दबाव अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मजबूत चक्रवाती परिसंचरण ऊपरी स्तरों तक सक्रिय है। यही प्रणाली इस सप्ताह पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी मौसम गतिविधियों उत्पन्न करेगी। इस वजह से वीकेंड में मेघालय, दक्षिण-पूर्व असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मैदानी इलाकों की अपेक्षा पर्वतीय जिलों में अधिक बारिश हो सकती है। भूस्खलन और छोटी-बड़ी नदियों में उफान का खतरा बना हुआ है, जिससे पहाड़ों पर फसल, सड़कों एवं बस्तियों को नुकसान हो सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इस बीच दिल्ली-

एनसीआर वाले के लिए एक राहत की खबर है। अगले एक हफ्ते तक मौसम सुहावना बना रहेगा और लगातार हल्की बारिश की फुहार लोगों को गर्मी और उमस से निजात दिलाएंगी। 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर का कहना है कि, जुलाई दिल्ली में अगस्त के बाद दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला महीना है। दिल्ली में मानसून की वर्षा मुख्य रूप से मानसून ट्रफ (न्यून दबाव की रेखा) पर निर्भर करती है, जो सामान्यतः गंगानगर से कोलकाता तक जाती है और दिल्ली के नजदीक दक्षिण में बनी रहती है। वर्तमान में यह ट्रफ देश के दोनों छोर पर स्थित दो चक्रवातीय परिसंचरणों को जोड़ रही है। एक परिसंचरण मध्य और दक्षिण राजस्थान पर स्थित है, जबकि दूसरा परिसंचरण झारखंड और छत्तीसगढ़ में बने पुराने निम्न दबाव क्षेत्र का शेष भाग है। जैसे-जैसे पूर्वी परिसंचरण पश्चिम की ओर बढ़ेगा, यह ट्रफ के साथ उत्तर-दक्षिण दिशा में डोलता रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार, 3 जुलाई तक ट्रफ दिल्ली से कुछ दूरी पर बनी रहेगी, इसलिए बारिश की संभावना कम ही रहेगी। अगर होगी भी तो बहुत हल्की छिटपुट और बहुत कम समय के लिए होगी। शुक्रवार (4 जुलाई) से यह ट्रफ उत्तर की ओर खिसकने लगेगी। इसके बाद बादलों बढ़ेंगे और घने होते जाएंगे। शनिवार और रविवार (5-6 जुलाई) को मौसम प्रणाली दिल्ली के अधिक अनुकूल होगी, जिससे अच्छी बारिश की संभावना बनेगी। यह बरसात की गतिविधि अगले सप्ताह की शुरुआत तक भी बनी रह सकती है। 5 से 9 जुलाई के बीच लगातार बादलों और रुक-रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। इन दिनों देश के पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भागों में मानसून अच्छी गति से सक्रिय है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर उपमंडलों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मौसमी वर्षा की कमी देखी जा रही है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पहले हुई अधिशेष वर्षा अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। पिछले 10 दिनों से इन क्षेत्रों में कोई बड़ी मानसूनी गतिविधि नहीं देखी गई है और यह स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट वेदर का अनुमान है कि दक्षिण भारत में सुस्त मानसून का प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी से उठने वाले निम्न दबावों का उत्तर की ओर रुख करना है। हाल के दिनों में अधिकतर मौसमी सिस्टम उत्तर दिशा की ओर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं के समांतर, इंडो-गंगेटिक मैदानों के साथ बढ़ते गए हैं। इससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पहले की कमी से उबरने में मदद मिली है। हालांकि बिहार अब भी 35 प्रतिशत वर्षा की भारी कमी से जूझ रहा है। एजेंसी का अनुमान है कि,दक्षिण भारत में मौसम प्रणाली की दिशा से कोई खास ऊर्जा नहीं मिल रही है जिससे इस क्षेत्र की मानसूनी गतिविधियां पुनः सक्रिय हो सकें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बारिश की स्थिति शांत बनी रहेगी। इस कारण आने वाले सप्ताह में यहां वर्षा की कमी और बढ़ सकती है। किसानों के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि फसल बुवाई के समय में वर्षा का न होना गंभीर संकट ला सकता है। यहां अच्छी बारिश के लिए इंतजार और लंबा हो सकता है।

भाजपा सरकार ने 61 लाख वाहनों को हटाने का अत्याचारी आदेश जारी किया है : मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के राजधानी में अधिक पुराने वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाने के हालिया आदेश को 'मध्यम वर्ग पर एक और हमला करार दिया। भाजपा सरकार ने इस कदम का समर्थन करते हुए इसे प्रदूषण नियंत्रण के अपने प्रयासों में एक आवश्यक प्रयास बताया है, जिसके बाद सिसोदिया का यह बयान आया है। सिसोदिया ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने दिल्ली की सड़कों से 61 लाख वाहनों को हटाने का अत्याचारी आदेश जारी किया है। यह शासन नहीं, यह 'फुलेरा की पंचायत है। जिन परिवारों ने अपने वाहनों का ध्यान रखा है, उन्हें अब दंडित किया जा रहा है। यहां तक कि जो वाहन 10,000 किलोमीटर से भी कम चले हैं, उन्हें भी अयोग्य माना जा रहा है। सिसोदिया ने नीति के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए पूछा, इससे किसे फायदा होता है? वाहन निर्माताओं, कबाड़ कारोबारियों और नंबर प्लेट कंपनियों को। क्या यह संयोग है कि यह आदेश टैक्सी किराए में वृद्धि की अनुमति दिए जाने से ठीक पहले आया? उन्होंने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने (भाजपा ने) रातोंरात अध्यादेश लाकर उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के आदेश की अवहेलना की। अब वे कहते हैं कि वे दिल्ली के 61 लाख परिवारों की मदद नहीं कर सकते। बता दें कि एक जुलाई से दिल्ली में 15 वर्ष से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक, तय अवधि पार कर चुके चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और दो पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना शामिल है, साथ ही संभावित जब्ती और गाड़ी उठाकर ले जाने का शुल्क भी देना होगा।

21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली। संसद का आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 13 और 14 अगस्त को दो दिवसीय अंतराल होगा। वहीं, किरेन रिजिजू ने आज बताया कि संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा। किरेन रिजिजू ने बुधवार शाम को एक पोस्ट के माध्यम से संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुरू में, सत्र को 12 अगस्त को समाप्त करने का कार्यक्रम था। रिजिजू ने कहा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने आगे कहा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। यद्यपि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, लेकिन आवश्यक तैयारियों के लिए दो दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। यह मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र होगा और इसके हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी दल कथित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले पर विशेष चर्चा की मांग सहित कई मुद्दे उठाने की योजना बना रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली और व्यापक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर कई दलों के समर्थन वाली सरकार ने भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष के आख्यानों का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सत्र से पहले एनडीए सहयोगियों की बैठक बुला सकती है ताकि अपनी रणनीति तय की जा सके। संसदीय परंपरा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को संसद परिसर से मीडिया को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान कई विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें बीमा से संबंधित विधेयक भी शामिल है।

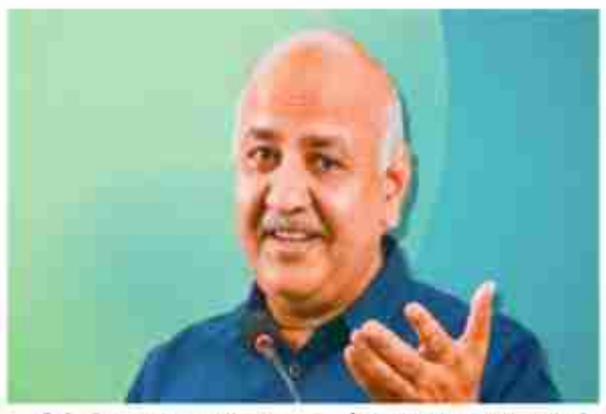

समाजसेवा, शिक्षा और समर्पण की जीवंत मिसाल-89 वर्षीय गुरुजी श्री ओमप्रकाश शर्मा का जन्मदिवस भव्य रूप से मनाया गया

नई दिल्ली (अजय कुमार चौधरी) लक्ष्मी नगर ट्रांस यमुना क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन की पहचान बन चुके 89 वर्षीय प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री ओमप्रकाश शर्मा जी का जन्मदिवस एक गरिमामय समारोह के रूप में लक्ष्मी नगर स्थित बेनी स्वीट्स में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह अवसर न केवल एक जन्मदिवस था, बल्कि समाज के लिए समर्पित एक सदी के प्रेरणास्रोत व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का शुभ क्षण भी था।

इस विशेष समारोह में राष्ट्र टाइम्स के संपादक श्री विजय शंकर चतुर्वेदी द्वारा श्री शर्मा जी को शॉल, प्रतीक चिन्ह और हार्दिक शुभकामनाओं सहित सम्मानित किया गया। उनकी जीवन यात्रा को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए चतुर्वेदी जी ने कहा कि ÷श्री ओमप्रकाश शर्मा जी न केवल एक शिक्षक रहे हैं, बल्कि उन्होंने सच्चे अर्थों में एक संजीवनी पुरुष की भूमिका निभाई है, जिन्होंने शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ कर जीवन भर पीड़ितों, जरूरतमंदों और उपेक्षितों के हित में कार्य किया।÷

इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। पूर्व पार्षद श्री बी.बी. त्यागी, संतोष पॉल, श्री राजेश पांडेय, रूपेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र चौधरी, अशोक शर्मा, एवं के. के. बेनी जैसे सम्माननीय गणमान्यजन उपस्थित रहे, जिन्होंने श्री शर्मा जी को पुष्पगुच्छ और शुभकामनाएं अर्पित कीं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगलकामना की।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, जिन्होंने आलोक भारती पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दीं, %गुरुजी% के नाम से पूर्वी दिल्ली, विशेष रूप से ट्रांस यमुना क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन समाज के उत्थान, गरीबों की सहायता, और नैतिक मूल्यों की स्थापना में बीता है। वे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समरसता और शिक्षात्मक प्रगति के सशक्त संवाहक रहे हैं।

पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से, श्री शर्मा जी ने लक्ष्मी नगर कॉम्प्लेक्स एवं आसपास के क्षेत्रों के विकास, स्वच्छता, सामुदायिक एकता और जनजागरूकता अभियानों में अग्रणी भूमिका निभाई है। वे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और आज भी समाज की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं।

उनका जीवन दर्शन यही रहा है ‡ ÷सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और शिक्षा उसकी पहली सीढ़ी।÷

उनके जन्मदिवस का यह आयोजन समाज के हर वर्ग के लिए यह संदेश था कि सेवा, समर्पण और सच्चाई से जीने वाले लोग कभी अप्रदान नहीं होते ‡ वे समाज के लिए सदैव ऊर्जा और प्रेरणा बने रहते हैं।

चौंकाने वाली रिपोर्ट : दिल्ली में हर साल खप जाती है कई करोड़ की अवैध शराब, सरकार ने उठाया सख्त कदम

नई दिल्ली। दिल्ली में खपाई जाने वाली अवैध शराब पर रोक नहीं लग पा रही है। दूसरे राज्यों में सस्ती होने के कारण प्रति वर्ष लाखों बोतल शराब दिल्ली में अवैध रूप से खप जाती है। आबकारी विभाग के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो कम से कम दो लाख से अधिक बोतल अवैध शराब एक साल में पकड़ी जाती है। इसमें ज्यादातर हरियाणा की बनी हुई शराब शामिल है। जिसकी कीमत अगर हम प्रति बोतल 500 भी लगा लें तो करीब 8 करोड़ से 10 करोड़ की बैठती है। पिछले सालों की बात करें तो पूर्व की आप सरकार ने आबकारी विभाग से राजस्व प्राप्त करने को लेकर जो उतावलापन दिखाया था वह उसी सरकार को गले की फांस बन गई थी। जिस आबकारी नीति में निजी ठेकेदारों को दिल्ली में शराब के ठेके दिए गए थे उसके माध्यम से आप सरकार ने यह दावा किया था इससे आबकारी राजस्व कई गुना बढ़ जाएगा। राजस्व तो नहीं बढ़ा मगर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता इस आबकारी नीति के चक्कर में जेल जरूर चले गए। उसके बाद दिल्ली में पूर्व की आबकारी नीति लागू कर दी गई। इस मामले में कई अधिकारी भी निलंबित हुए, कुछ को जेल तक जाना पड़ा था। उसके बाद से आबकारी विभाग में हालात ऐसे बन गए कि यहां अधिकारी आने को तैयार नहीं थे या फिर जो आए भी वे काम करने को तैयार नहीं थे। पिछले तीन साल में स्थिति ऐसी ही बनी रही। इस दौरान शराब की निगरानी में भी कमी आई। जो आबकारी विभाग की टीमें लगातार छापेमारी करती थी और दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहती थी कि जिससे दिल्ली में अब शराब का आना बंद किया जा सके। इस कार्य में भी काफी कमी आई। बहरहाल अब हालात बदल रहे हैं दिल्ली में भाजपा की सरकार है, ऐसे में आबकारी विभाग में अधिकारी भी इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए हिम्मत दिखा रहे हैं। कुछ माह पहले आबकारी विभाग ने निगरानी कार्य के लिए सरकार से कम से कम 50 कर्मचारियों की तैनाती की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही सरकार इस बारे में आबकारी विभाग की शक्ति बढ़ाने जा रही है।

लागू होते ही हाईकोर्ट पहुंचा नई ईंधन नीति का मामला, दिल्ली सरकार-वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब-तलब

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू नए नियम पर दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन कोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने मामले को सितंबर महीने में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे निर्देशों को लागू करना पेट्रोल पंप मालिकों की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वे कोई राज्य एजेंसी नहीं है और न ही उनके पास कानून प्रवर्तन की वैधानिक शक्ति है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2025 से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न दें। यह निर्णय सीएक्यूएम के आदेश पर लिया गया है। आदेश के क्रियान्वयन में कानूनी चुनौतियां, व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर वे अनजाने में किसी ईएलवी को ईंधन दे देते हैं, तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत दंडित किया जा रहा है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आयोग दंड का भय दिखाकर ऐसे नियम लागू करा रहा है, जिससे पंप मालिकों में भारी असमंजस और डर का माहौल बन गया है। नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने किसानों के हित में पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध में राहत देने और ई-वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि गांवों में कई गरीब व किसान परिवारों की आजीविका पुरानी गाड़ियों पर निर्भर है। ऐसे में इन पर रोक से रोजगार पर असर पड़ेगा। प्रदूषण की असली वजह केवल पुरानी गाड़ियां नहीं हैं। दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए समयसीमा बढ़ाए और दोपहिया व छोटी कारों के बदले ई-वाहनों पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दे।

रोहिणी में 22 एकड़ में बनेगा आधुनिक वेयरहाउस, लागत होगी करीब 195 करोड़; डीडीए ने शुरू की बोली प्रक्रिया

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रोहिणी के सेक्टर-36 में 22 एकड़ जमीन पर आधुनिक वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रण (आरएफपी) जारी किया गया है, जिसका मकसद दिल्ली को लॉजिस्टिक्स और व्यापार का बड़ा केंद्र बनाना है। परियोजना की लागत कम से कम 195 करोड़ रुपये होगी। इसे लाइसेंस शुल्क के आधार पर विकसित किया जाएगा। डीडीए ने इस परियोजना को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। बोली लगाने वालों को तकनीकी और वित्तीय योग्यता पूरी करनी होगी, जिसमें पिछले प्रोजेक्ट का अनुभव और वित्तीय स्थिरता शामिल है। बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए गैर-वापसी योग्य शुल्क और बिड सिक्योरिटी जमा करनी होगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्राथमिकता मिलेगी। डीडीए ने लाइसेंसधारी को सख्त शर्तों का पालन करने को कहा है, जिसमें परियोजना को समय पर काम पूरा करना और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना शामिल है। परियोजना पूरी होने पर यह दिल्ली के व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई गति देगा। डीडीए के अधिकारियों ने कहा है कि यह परियोजना दिल्ली को आर्थिक रूप से और मजबूत करेगी। ये दिल्ली को आधुनिक व्यापारिक हब बनाने की दिशा में अहम है। वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में ऊर्जा-कुशल डिजाइन, पर्याप्त बिजली बैकअप और हरित क्षेत्र होंगे। यह परियोजना पर्यावरण नियमों और दिल्ली शहरी कला आयोग की मंजूरी के तहत होगी। यह साइट रिठाला (रेड लाइन) और समयपुर बादली (येलो लाइन) मेट्रो स्टेशनों से 10 किमी के दायरे में है और रोहिणी के सेक्टर-10 के औद्योगिक क्षेत्रों से 5 किमी दूर है। आसपास आवासीय क्षेत्र, डीडीए हाउसिंग और महेश्वरी अस्पताल जैसे स्वास्थ्य केंद्र इसे और आकर्षक बनाते हैं।

क्या बदल जाएगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम? सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक रूप से केंद्रीय रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर महाराजा अग्रसेन के सम्मान में प्रतिष्ठित पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का आग्रह किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे अपने पत्र में गुप्ता ने प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक शख्सियत के लिए उचित श्रद्धांजलि बताया, जो सामाजिक और आर्थिक आदर्शों का प्रतीक है, जो लाखों लोगों के मन में गूंजते रहते हैं। अपने संदेश में गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन को एक पूजनीय व्यक्ति बताया, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक निष्पक्षता और सामुदायिक कल्याण के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री ने उनकी स्थायी विरासत पर प्रकाश डाला, खासकर दिल्ली में, जहां उनके अनुयायियों और वंशजों ने शहर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेशन का नाम बदलने से न केवल महाराजा अग्रसेन की विरासत का सम्मान होगा, बल्कि उन अनगिनत दिल्लीवासियों की भावनाओं का भी पता चलेगा जो उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों का प्रतीक होगा और राजधानी में समुदाय की गहरी मौजूदगी को मान्यता देगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे दिल्ली जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1864 में हुई थी और इसने कलकत्ता (अब कोलकाता) से ब्रॉड-गेज ट्रेन सेवा के साथ परिचालन शुरू किया था। आज, यह देश के सबसे व्यस्त और सबसे ऐतिहासिक रेलवे केंद्रों में से एक है, जो प्रतिदिन हजारों यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। जबकि इस पहल को वरिष्ठ भाजपा नेताओं से समर्थन मिला है, रेल मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह प्रस्ताव अब सार्वजनिक चर्चा में आ गया है और विरासत, सार्वजनिक स्मृति और क्षेत्रीय पहचान पर व्यापक चर्चा को आमंत्रित कर सकता है।

ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पारित बनाम मस्क की नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ देख रही थी कि पिछले कुछ महीनों से कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनियाँ में चल रहे अनेकों युद्धों को रोकने के लिए रुचि दिखा रहे है, जिसमें शामिल हैरानके 12 बार दोहराना कि भारत-पाक युद्ध विराम उन्होंने करवाया,सीरिया से प्रतिबंध हटाना,रूस यूक्रेन युद्ध विराम में रुचि,ईरान इजरायल में युद्ध विराम सहित इस दिशा में अनेकों कार्य कर रहे है। हालांकि इसके बावजूद युद्ध विराम देशों में तनाव तल्ख बढ़ी हुई है, परंतु उनकी कोशिशों को रेखांकित करना होगा, उनको नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद को भी रेखांकित करना होगा। हालांकि इस पुरस्कार के दावेदार अनेकों लोग अनेकों वर्षों से वैश्विक शांति पर काम कर रहे है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। अभी 1जुलाई 2025 को अमेरिका में एक तरह से ट्रंप-मस्क के बीच भिड़ंत जुबानी शाब्दिक जंगनाली एक तरह से गृहयुद्ध में गिर गए हैं।मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि जिस दोस्ती के साथ ट्रंप-मस्क चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित कर जीत हासिल किए व अमेरिका को मेकिंग ग्रेट अमेरिका अगेन के वादे के निपटेत तगड़ी भिड़ंत कर जुबानी जंग बाजी कर अमेरिका के मतदाताओं का विश्वास भंग करके माहौल खराब करने की ओर अग्रसर कर अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक स्थिति सहित अपने रुतबे को कम कर दुनियाँ में कम करने से बेहतर होगा कि आपसी समझौता कर स्थिति को गंभीरता की ओर जाने से बचने की जरूरत है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप-मस्क की लड़ाई, अमेरिकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण दुष्परिणाम ला सकती है-जनहित में मतभेद सुलझाना जरूरी। साथियों बात अगर हम ट्रंप-मस्क के टकराव को राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो, यह एक दिलचस्प प्रश्न है।अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच का विवाद एक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के टकराव का प्रतीक है।डोनाल्ड ट्रंप, एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, जिनके पास एक मजबूत समर्थक आधार है। उनकी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, मस्क एक सफल उद्योगपति और व्यवसायी हैं,जिनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। उनकी कंपनियां, जैसे कि टेस्ला और स्पेसएक्स, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं और उनके पास एक मजबूत आर्थिक आधार है। इस विवाद में, यह कहना मुश्किल है कि किसकी शक्ति अधिक प्रभावी होगी। लेकिन यहाँ कुछ बातें है जिन पर विचार किया जा सकता है।ट्रंप की राजनीतिक शक्ति और समर्थक आधार उनके लिए एक मजबूत पक्ष हो सकता है।मस्क की आर्थिक शक्ति और उनकी कंपनियों की वैश्विक पहुंच उनके लिए एक मजबूत पक्ष हो सकती है।हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।इस विवाद के निपटारे में।ट्रंप और मस्क के बीच विवाद का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है (1) बाजार की अस्थिरता- टेस्ला और अन्य कंपनियों के शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है,जिससे बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है।

(2) निवेश पर प्रभाव- यदि विवाद बढ़ता है, तो निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है,जिससे निवेश में कमी आ सकती है।(3) आर्थिक विकास पर प्रभाव- यदि विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर सकता है। (4) रोजगार पर प्रभाव- यदि टेस्ला जैसी कंपनियों को नुकसान होता है, तो इससे रोजगार के अवसरों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी और विविध है, और एक विवाद का इसके समग्र प्रदर्शन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। साथियों बात अगर हम ट्रंप-मस्क की तगड़ी भिड़ंत व जुबानी जंगबाजी की करें तो,मस्क और ट्रंप के बीच कर छूट और खर्चे में कटौती को लेकर वाकयुद्ध फिर से शुरू हो गया है। मस्क का कहना है कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ पर इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर हमला बोला है। मस्क ने रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा पारित किए गए,बिल की आलोचनाकी। उनका कहना है कि इससे नौकरियां खत्म हो जाएंगी और उभरते उद्योग पिछड़ जाएंगे। ट्रंप ने मस्क पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मस्क को इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी के बिना उन्हें अपना कारोबार बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ सकता है।

संभवतः अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खास सिपहसालार रहे मस्क को अब ट्रंप के फैसले रास नहीं आ रहे हैं। इन दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। यह विवाद टैक्स में छूट और खर्चों में कटौती को लेकर है। मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के बिल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बिल नौकरियों को खत्म कर देगा। यह उन उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। मस्क ने एक्स पर लिखा कि यह बिल रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या होगा। सीनेट में इस बिल पर लंबी बहसचली व बिल पारित हो गया,मस्क ने कहाथा कि वह अगले साल कांग्रेस के उन सदस्यों को हटाने के लिए काम करेंगे जो इस बिल को पास करेंगे। कुछ घंटे बाद, मस्क ने एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा था,अगर यह बिल पास हो जाता है, तो अगले दिन अमेरिका पार्टी% का गठन किया जाएगा।उन्होंने आगे कहा,हमारे देश को डेमोक्रेट - रिपब्लिकन से अलग%एक पार्टी के विकल्प की जरूरत है ताकि लोगों को वास्तव में अपनी बात रखने का मौका मिले। मस्क के इस पोस्ट को एक्स पर 3.2 करोड़ बार देखा गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मस्क जानते है कि वे ईवी जनादेश के खिलाफ है। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ट्रम्प ने लिखा,एलन को शायद इतिहास में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी मिलती है, और बिना सब्सिडी के एलन को शायद अपना कारोबार बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा।राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इससे देश के लिए कुछ लागत बचत हो सकती है।

उन्होंने पोस्ट किया,कोई और रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार उत्पादन नहीं होगा और हमारे देश के बहुत सारे पैसे बचेंगे। शायद हमें डीओजीई को इसपर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए? बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते है! साथियों बात अगर हम 1 जुलाई 2025को देर रात सीनेट में पारित वन बिग ब्यूटीफुल बिल की करें तो, ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट से मामूली अंतर के साथ पास हो गया। इस बिल को पास कराने में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अहम कड़ी साबित हुए। ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती वाले इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े, जिसके बाद वेंस ने अपना वोट डालकर इसे मंजूरी दिलाई। मुकाबला तब देखने को मिला, जब सीनेट के बहुमत नेता जॉन थ्यून ने दो उदारवादियों को अपने पक्ष में कर लिया, जो डेमोक्रेट्स के पक्ष में झुके हुए थे। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बिल पारित करने के लिए 4 जुलाई की समय सीमा दी है, जिसमें सैन्य खर्चे में 150 बिलियन डॉलर की वृद्धि और अमेरिकी राष्ट्रपति के सामूहिक निर्वासन कार्यक्रम का प्रावधान है।बिल में ट्रंप के पहले कार्यकाल के कर कटौती में 4.5 ट्रिलियन डॉलर का विस्तार करने का प्रावधान है।इसमें मेडिकेड स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पर 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक की कटौती का प्रस्ताव है। इससे लगभग 8.6 मिलियन कम आय वाले और विकलांग अमेरिकियों को उनके स्वास्थ्य कवरेज से वंचित होना पड़ सकता है। यह विधेयक हरित ऊर्जा टैक्स क्रेडिट सैकड़ों डॉलर भी वापस लेताहै,पर्यावरण अधिवक्ताओं ने ईवी कर क्रेडिट को वापस लेने पर चिंता जताई है। गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा विदेशों में पैसे भेजने पर टैक्स लगाने का प्रावधान है। प्रारंभिक प्रस्तावइस बिल में मूल रूप से 5पर्सेंट रेमिटेंस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके 3.5पर्सेंट कर दिया गया, जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष ने बताया है। वर्तमान संशोधन सीनेट ने अब इसे और कम करके 1 पर्सेंट कर दिया है।

बहस : मतदाता की जांच या 'वोट का अधिकार' छीनने की साज़िश!

अमरेंद्र कुमार राय

चुनाव आयोग ने बीती 24 जून को एक आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि बिहार सहित छह राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन परीक्षण किया जाएगा। जिन पांच और राज्यों में मतदाता सूचियों की गहन समीक्षा की जाएगी उनमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल है। ये सभी वो राज्य हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने है। जिन पांच राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां अभी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं है। क्योंकि उन राज्यों के पास इसके लिए अभी समय है। लेकिन बिहार में तो अगले तीन चार महीनों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा के बाद जो मतदाता सूची तैयार की जाएगी उसी के आधार पर चुनाव कराये जाएंगे। 24 जून को जारी आदेश के अनुसार यह कार्य 25 जून से शुरू हो जाएगा और तीस सितंबर तक कार्य पूरा करके नई मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी। यानी चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कार्य शुरू कर दिया है और करीब एक हफ्ता हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे और 25 जुलाई तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे। बिहार में करीब आठ करोड़ मतदाता है। मोटे तौर पर इन मतदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक- जिनकी उम्र 38 साल से ज्यादा है। यानी जो 1987 से पहले के पैदा हुए है। दूसरे वे जो 1987 और 2003 के बीच पैदा हुए हैं यानी जिनकी उम्र 20,22 साल से लेकर 37 साल तक है। तीसरे वे जो 2004 के बाद पैदा हुए है और जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है। भारत में 18 साल से ज्यादा के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। जो 38 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए मुसीबत कम है। उन्हें एक साधारण फॉर्म भरना है, अपनी फोटो चिपकानी है और सरकारी कर्मचारी को दे देना है। जो 1987 के बाद और 2003 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपने साथ ही अपने माता-पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना है। जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपना और अपने माता-पिता दोनों का ही जन्म और निवास प्रमाण पत्र देना है। सरसरी तौर पर देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आती। बल्कि अच्छा ही लगता है। अभी तक मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत होती रही है। अब अगर चुनाव आयोग विशेष गहन अभियान चलाकर इसे दुरुस्त करता है तो इसमें बुराई क्या है ? बल्कि यह अच्छा ही है। लेकिन जैसे ही इस पर विचार करते हैं इसकी गंभीरता और परेशानियां साफ-साफ दिखाई पड़ने लगती है। बिहार में करीब आठ करोड़ मतदाताओं में से 38 साल से ज्यादा उम्र के करीब सवा तीन करोड़-साढ़े तीन करोड़ मतदाता हैं।

इनके लिए शर्त यह है कि इनमें से जिस किसी का भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है उन्हें बस फॉर्म भरना है और अपना फोटो चिपका कर सरकारी कर्मचारी (बीएलओ) को दे देना है। लेकिन अगर जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनका नाम वोटर लिस्ट में तो है लेकिन आधा-अधूरा नाम है तो उन्हें अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए की सवा तीन करोड़ मतदाताओं में से तीन करोड़ का नाम मतदाता सूची में है और करीब 25 लाख का नहीं है तो उन 25 लाख को अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। सवाल यह है कि जन्म प्रमाण पत्र देंगे कहां से ? बनवाया हो तब न देंगे? यहां तो जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाते बहुत कम लोग हैं।

एक जानकारी के मुताबिक बिहार में सिर्फ 2.8 प्रतिशत लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाये हैं। फिर बाकियों का क्या होगा? महीने भर में कितने लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे ? दूसरी श्रेणी में 1987 के बाद और 2003 तक पैदा हुए लोग हैं। इन्हें अपने साथ ही अपने माता-पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म प्रमाण पत्र की हालत आपने देखी कि महज 2.8 प्रतिशत लोगों के पास है। दूसरा विकल्प जन्म प्रमाण पत्र का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है। बिहार में कुल 12-13 प्रतिशत लोगों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तीसरा विकल्प जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र भी 20-25 प्रतिशत लोगों के पास ही होने का अनुमान है। क्योंकि जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने की उम्मीद होती है बस वे लोग ही जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। सवर्णों को कोई लाभ नहीं मिलता तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र होता ही नहीं। बाकी बचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोग तो इनमें भी सरकारी लाभ पाने वाले ही जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जो मुश्किल से 20 से 30 प्रतिशत ही होंगे। इस वर्ग में बिहार के सबसे ज्यादा मतदाता हैं करीब चार, साढ़े चार करोड़। ये सब लोग नई मतदाता सूची समीक्षा में प्रभावित होने वाले हैं। अगर 2.8 प्रतिशत जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले, 12-13 प्रतिशत हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जमा करने वाले और 25-30 प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों को जोड़ दें तो भी ये आंकड़ा 50 प्रतिशत को नहीं छूता। इस तरह इस वर्ग से भी दो-सवा दो करोड़ लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने से वंचित रह जाएंगे। जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है उनके सामने तो और बड़ी समस्या है। उन्हें अपने साथ ही माता और पिता दोनों का ही जन्म प्रमाण पत्र देना है, जो कि इनके लिए बेहद मुश्किल होगा। इस तरह आप देखें तो आठ करोड़ मतदाताओं में से करीब पांच करोड़ मतदाताओं के बाहर होने का खतरा है। यानी वो अगले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इसमें खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने नागरिकों की पहचान के जो सबसे प्रमुख तीन दस्तावेज हैं उनमें से किसी को भी नहीं माना है।

सबसे ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड होता है। बिहार में 88 प्रतिशत लोगों के पास आधार कार्ड है। चुनाव आयोग चाहता तो आधार कार्ड को जन्म तिथि और निवास के दस्तावेज के रूप में मान्यता दे सकता था। इस तरह 88 प्रतिशत लोगों को मतदान का अधिकार एक झटके में मिल सकता था। बाकी जो बचते उनका आधार कार्ड बनवाया जा सकता था। दूसरा सबसे ज्यादा सुलभ दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान पत्र है। यह भी काफी संख्या में लोगों के पास है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे भी मान्यता नहीं प्रदान की है। तीसरा थोड़ा मुश्किल लेकिन फिर भी सुलभ दस्तावेज राशन कार्ड है लेकिन चुनाव आयोग को इस पर भी भरोसा नहीं। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग गरीब, मजदूर और वंचित तबके को मतदान के अधिकार से बाहर करना चाहता है। इसीलिए उसने ये आदेश जारी किया है। बिहार में तो अगले चार महीने में चुनाव होने हैं। महीने भर में इस प्रक्रिया को ही पूरा नहीं किया जा सकता है। पीछे बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। उसमें किसी नागरिक को कोई दस्तावेज नहीं देना था तब भी उसमें पांच महीने का समय लगा। यहां तो नागरिकों को दस्तावेज देना है, फॉर्म भरना है, फोटो चिपकाना है फिर यह कार्य महीने भर में कैसे हो सकता है ? ऊपर से यह बरसात का मौसम है। बिहार के 73 प्रतिशत हिस्सों में जल भराव या बाढ़ की स्थिति होती है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाएंगे या चुनाव आयोग को दस्तावेज देंगे ? आपको मालूम है देश में पहले बहुत कम लोगों को मताधिकार प्राप्त था। अंग्रेजों के जमाने में भारतीयों को मत देने के अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार के जरिये मताधिकार को बढ़ाया गया। 1935 में इसे और विस्तृत किया गया। फिर भी बहुत कम भारतीयों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो पाया था। एक खास वर्ग ही था जो इसमें शामिल था। वे लोग जो कर अदा करते थे, शहरों में निवास करते थे या फिर शिक्षित थे वे ही मत दे सकते थे।

आजादी के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मत का अधिकार दिया गया। चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। बाद में मताधिकार की आयु घटाकर 21 से 18 साल कर दी गई। लेकिन अब इस सरकार-चुनाव आयोग ने पिछले दरवाजे से लोगों के मताधिकार छीनने का अभियान शुरू कर दिया है।

राजनीतिज्ञों की हिंसक प्रवृत्ति!

स्वतन्त्र भारत की राजनीति में जिस प्रकार का नैतिक पतन हम देख रहे हैं उसे कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि समाज के नजरिये से देखें तो जैसा समाज होगा वैसे ही लोग राजनीति में आकर उसका चरित्र बनायेंगे और यदि राजनैतिक नजरिये से देखें तो जो राजनीति का चरित्र होगा वैसा ही समाज बनेगा परन्तु भारतीय दृष्टि कहती है कि 'यथा राजा-तथा प्रजा'। इसका अर्थ यही है कि जैसे लोग राजनीति में आयेंगे वैसा ही वे समाज भी बनाने का प्रयास करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतन्त्र है और यहां हर पांच साल बाद लोगों के हाथों में सत्ता परिवर्तन की चाबी रहती है। इसका मतलब यही है कि राजा जनता के बीच से ही उठकर आता है न कि किसी महारानी के पेट से जन्म लेकर किन्तु भारत की राजनीति में जिस प्रकार परिवारवाद प्रभावी है उसने लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए ही चुनौती खड़ी कर रखी है क्योंकि परिवार की विरासत संभालने वाले राजनीतिज्ञ तर्क देते हैं कि जब डाक्टर का बेटा डाक्टर हो सकता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है तो राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं हो सकता, जबकि लोकतन्त्र में जनता ही किसी राजनैतिक परिवार की विरासत संभाले व्यक्ति को बहुमत से चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। ऐसे तर्क हम उन नेताओं से ही प्रायः सुनते हैं जो विशिष्ट जातियों के नेता होते हैं अर्थात जातिवादी दलों की कमान संभाले होते हैं। इस जातिगत राजनैतिक व्यवस्था के चलते भारत का लोकतन्त्र ऐसे राजतन्त्र में बदल जाता है जिसमें राजा का मुंह देखकर ही आम जनता स्वयं को धन्य समझने लगती है और यह भूल जाती है कि उसे एक वोट का अधिकार दुनिया की ऐसी नियामत है जिसके प्रयोग से वह खुद भी राजा बन सकता है। सौभाग्य से भारत का प्रधानमन्त्री आज एक ऐसा व्यक्ति है जो बचपन में कभी चाय बेचा करता था। श्री नरेन्द्र मोदी का प्रधानमन्त्री बनना ही भारत के लोकतन्त्र की असलियत है जिसे परिवारवादी दल पचा नहीं पा रहे हैं । मगर आज असली सवाल राजनीति में आये नैतिक पतन का है। पतन इस हद तक आ चुका है कि मन्त्री खुद सरकारी अफसरों को पीट रहे हैं और लहूलुहान कर रहे हैं। जो मन्त्री जनता द्वारा चुना गया होता है वह अपनी कलम की जगह हाथों से काम ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में मन्त्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो अधिकारियों की पिटाई की जिनमें से एक तो अभी तक अस्पताल में दाखिल है। मन्त्री के खिलाफ प्राधिकरण की एक सड़क परियोजना के प्रबन्धक श्री अचल जिन्दल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि श्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र में सड़क परियोजना के चलते उसके किनारे बने मकान के ढह जाने पर आक्रोशित होकर उसके साथ ही इलाके के 27 वर्षीय इंजीनियर योगेश वर्मा की भी पिटाई की और दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। दूसरी घटना ओडिशा की है जहां कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने प्रादेशिक नागरिक सेवा के अधिकारी श्री रत्नाकर साहू के कार्यालय में घुसकर उन्हें दफ्तर से बाहर घसीट कर बुरी तरह पीटा। यह घटना भुवनेश्वर की है। अधिकारी रत्नाकर साहू भुवनेश्वर महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त पद पर आसीन हैं। यह कार्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया जबकि जिस मन्त्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ शिमला में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई वह कांग्रेस पार्टी के हैं। भारतीय राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि हिंसक तरीके अपनाने का दम भरने वाली कोई भी राजनैतिक पार्टी चुनावों में भाग नहीं ले सकती। श्री साहू ने थाने में छह अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें कहा गया है कि इन लोगों ने उनसे यह कहा कि क्या उन्होंने भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान से माफी मांगी या नहीं। प्रधान भुवनेश्वर भाजपा के नेता हैं।

उपरोक्त दोनों घटनाएं बताती हैं कि राजनीति में हिंसक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं और वे मन्त्री तक बन रहे हैं। जिस समय श्री साहू को दफ्तर से घसीट कर बाहर लाया गया उस समय वह आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। आम जनता के सामने इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर आखिरकार राजनैतिक कार्यकर्ता क्या पैगाम देना चाहते हैं? असली पैगाम यही है कि राजनीति गुंडा तत्वों का शरण स्थल बन रही है। इस बारे में पश्चिमी विचारक को उद्धृत किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार की हिंसक राजनैतिक प्रवृत्ति को रोकना होगा क्योंकि सरकारी अफसर भी हमारे लोकतन्त्र का एक स्तम्भ होते हैं।

चुने हुए प्रतिनिधि इन्हीं के माध्यम से विकास व प्रगति के कार्यों को कराते हैं। भारत के लोकतन्त्र की कार्यपालिका एक मजबूत खम्भा है जो अपना कार्य संविधान की शपथ लेकर ही करती है। मगर इस स्तम्भ को खुद राजनीति का शिकार प्रायः बनाया जाता है और जबरन उससे राजनीतिज्ञ अपने मनमाने फैसले लागू करने की जिद करते हैं। इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है और उसका चरित्र भी इसी सांचे में ढलता चला जाता है। जबकि लोकतान्त्रिक राजनीति में शालीनता इसका गहना होती है। जो भी व्यक्ति राजनीति के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है उसका जीवन एक खुली किताब बन जाता है। वह इसीलिए है जिससे जनता राजनीतिज्ञों के जीवन से प्रेरणा ले सके और सभ्य व सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सके। महात्मा गांधी की दृष्टि यही थी। अतः बहुत जरूरी है कि हम राजनीति में हिंसक प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को आगे न बढ़ने दें मगर जातिवादी पर परिवारवादी राजनीति के चलते यह कार्य दुष्कर होता जा रहा है।

भारत-चीन सीमा विवाद

भारत और चीन विश्व की 2 प्राचीन एवं महान सभ्यताओं के देश हैं। दोनों देश लगभग एक साथ ही स्वतंत्र हुए। आजादी के बाद से ही चीन और भारत में सीमा विवाद ने एक ऐसी समस्या को जन्म दिया जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। कम्युनिस्ट देश चीन के बारे में पूरी दुनिया में यह धारणा बनी कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते दूसरे देशों की जमीन पर एक-एक इंच करके आगे बढ़ता है और बाद में जमीन कब्जा लेता है। भारत चीन की घुसपैठ का कई बार शिकार हो चुका है। दोनों देशों के संबंध भी काफी जटिल रहे हैं। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शांत होने के बाद संबंधों में सुधार होने की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी थी। अब चीन ने कहा है कि भारत के साथ चीन की सीमा विवाद जटिल है लेकिन इसके समाधान में समय लगेगा। हालांकि वह परिसीमन पर चर्चा करने के लिए तैयार है ताकि सीमा क्षेत्र पर शांति बनी रहे। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की ओर से ये बयान तब आया है जब 26 जून को भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षामंत्री डोंग जुन के बीच क्विंगदाओ में हुए एससीओ डिफेंस मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर तनाव कम करने के लिए सीमा के स्पष्ट सीमांकन के लिए एक संरचित रोडमैप का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाने और सीमांकन के लिए मौजूदा तंत्र को सक्रिय करने का आह्वान किया था। बीजिंग में जब मीडिया ने चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर टिप्पणी करने को कहा तो माओ ने कहा कि दोनों देशों ने पहले ही विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र स्थापित कर लिया है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच तंत्र 1993 में स्थापित किया गया था। 1993 के समझौते के तहत दोनों देशों द्वारा सीमा प्रबंधन का काम किया गया और यह समझौता दोनों देशों को सीमा पर गश्त का अधिकार देता है। दूसरा समझौता 1996 में किया गया, जिसके तहत सीमा पर बल प्रयोग नहीं करने का प्रावधान किया गया। सीमा विवाद पर पिछले साल विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं वार्ता हुई थी। इस बैठक में लद्दाख सीमा पर गतिरोध दूर हुआ और दोनों देशों ने डिस एंगेजमेंट समझौते की पुष्टि की। चीन की सेनाओं का एलएसी पर पूर्व स्थिति में जाना मोदी सरकार की बड़ी जीत रही। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद तीन सैक्टरों में बंटी हुई है-पश्चिमी सैक्टर यानी जम्मू-कश्मीर, मिडिल सैक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सैक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। भारत पश्चिमी सैक्टर में अक्साई चिन पर अपना दावा करता है लेकिन ये इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था।

सम्पादकीय...

माधवदास वैरागी कैसे.....

बंदा सिंह बहादुर जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और उनका जन्म कश्मीर के पुंछ गांव के राजौरी में 1670 ई. को हुआ। बचपन से ही वह फारसी, संस्कृत, पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान रखते थे और युद्ध कला में भी निपुण थे। एक दिन शिकार के दौरान उनका तीर एक गर्भवती हिरणी को लगने से तड़प-तड़प कर उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसे मृत अवस्था में देख वह वैराग्य की अवस्था में आ गये और सब कुछ त्याग जंगल की ओर चल पड़े। साधु जानकी दास के संपर्क में आने के बाद उन्होंने नाम बदलकर माधवदास रख लिया। कुछ समय बाद हजूर साहिब के पास एक स्थान पर उनकी मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई और उसी मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया और गुरु जी के बंदा बन गए। मुगल शक्ति के ना हारने और भारतीयों द्वारा उन्हें ना हरा पाने का सदियों पुराना भ्रम तोड़कर रख दिया। उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर गुरु जी ने बंदा सिंह को बहादुर का खिताब दिया तभी से उन्हें बंदा सिंह बहादुर कहकर सम्बोधन किया जाने लगा। इतिहास गवाह है कि बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी और गुरु साहिब के साहिबजादों का बदला भी मुगलों से लिया मगर अन्त में मुगलों ने उन्हें कैद कर कुतुबमीनार के सामने स्थान पर अनेक कष्ट देकर जबरन इस्लाम कबूलने को कहा गया लेकिन जब वह नहीं माने तो उनके 6 वर्षीय पुत्र अजय सिंह का कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाला गया। जो शायद पृथ्वी लोक पर अकेली ऐसी घटना है। किसी के भी बच्चे को अगर जरा सी भी चोट लग जाये तो हमारे हाथ-पांव फूल जाते हैं, पर धन्य है बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने हर कष्ट तो सह लिया, पर हार नहीं मानी, आखिरकार उनकी शहादत हो गई। मगर आज दुख होता है जब कुछ एजेंसियां और सरकारों को चलाने वाले अफसरशाही सिख विरोधी सोच के लोग उन्हें बन्दा वैरागी बताकर यह साबित करने में लगे हैं कि वह सिख नहीं थे। मगर उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक वह वैरागी थे उनमें बहादुरी नहीं थी। शक्ति उन्हें अमृतपान के बाद आई इसलिए उन्हें सम्बोधन करते समय बाबा बन्दा सिंह बहादुर का प्रयोग करना चाहिए वैरागी का नहीं। आज समय ऐसा आ गया है लोग अपनी मातृ भाषा में बातचीत करना तौहीन समझते हैं। 99 प्रतिशत सिखों के घरों में भी बातचीत का माध्यम अंग्रेजी या फिर हिन्दी बन चुका है। बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिलाने के चलते हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा कान्वेंट स्कूलों में पढ़े ताकि आगे चलकर वह अपना भविष्य बेहतर बना सके मगर शायद वह यह भूल जाते हैं कि कान्वेंट स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी तो सीख जाएंगे मगर अपनी मातृ भाषा का ज्ञान उन्हें नहीं मिल सकेगा और जब बच्चे मातृ भाषा भाव गुरमुखी ही नहीं सीखेंगे तो पाठ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी के चलते आज युवा वर्ग सिखी का त्याग करता चला जा रहा है। पहले समय में भले बच्चे स्कूलों में मातृ भाषा न भी सीखें, पर परिवार बड़े होने के चलते दादा-दादी के द्वारा ही बच्चों को अपनी भाषा, गौरवमयी विरसे की जानकारी दी जाती थी, अब तो वह भी नहीं रहा। माता-पिता बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के चक्कर में दौड़- धूप की जिन्दगी व्यतीत करने को मजबूर हैं, उनके पास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का समय ही नहीं है। ऐसे में गुरमत कैंप ही एकमात्र विकल्प बचा है जिसमें बच्चे गुरमुखी, सिख इतिहास, कीर्तन आदि की शिक्षा ले सकते हैं मगर उनमें भी बहुत कम अभिभावक ही अपने बच्चों को भेजते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी द्वारा इस बार 230 के करीब गुरमत कैंप गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए लगाए गए, इसके साथ ही एक विशेष कैंप उ.प्र. के अनूपशहर जहां गुरु हरिराय साहिब जी का आनन्द कारज हुआ था, उसी गुरुद्वारा साहिब में लगाया गया जिसमें 40 दिनों के लिए बच्चों को रखकर उन्हें अमृतवेले उठाया गया, स्नान के पश्चात पाठ, कीर्तन, पंजाबी सिखलाई की क्लास ली गई, जिसका परिणाम यह निकला कि आज वह बच्चे जिन्हें गुरमुखी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उड़ा-ऐड़ा तक नहीं आता था, मात्र 40 दिनों के भीतर वह ना सिर्फ गुरमुखी सीख गए बल्कि पाठ और कीर्तन भी करने लगे। इनमें कई बच्चे तो बहुत ही छोटी उम्र के भी थे। दिल्ली कमेटी द्वारा बकायदा उन्हें स्मृति चिन्ह एवं सर्टीफिकेट भी दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि सिख वह मार्शल कौम है जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक जब भी देश को आवश्यकता हुई सबसे आगे बढ़कर कुर्बानियां दीं। सिखों की गिनती भले ही इस देश में 2 प्रतिशत हो मगर उनकी कुर्बानियां 85 प्रतिशत से अधिक रही हैं, यहां तक कि अंग्रेज हकूमत भी सिखों की बहादुरी के सामने घुटने टेक दिया करती थी। सारागढ़ी का युद्ध आज भी याद है जब मात्र कुछ सिख फौजियों ने हजारों की दुश्मन फौज का निडरता के साथ सामना किया। आज भी देश की सरहदों पर सिख सैनिक सीना तानकर देश की रक्षा हेतु तैनात हैं। आजादी के बाद से पंजाब का युवा सिख या तो खेती करता या फिर फौज में जाने पर गर्व महसूस करता। हालांकि बीते समय में सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियों के चलते सिखों की सेना में भर्ती कम हुई है क्योंकि सरकारी नीति के अनुसार राज्य की संख्या के आधार पर भर्ती की जाने लगी जिसमें पंजाब से ज्यादा फौजी दूसरे राज्यों से आने लगे। आज भी अनेक ऐसे सिख परिवार हैं जिनके लड़के ही नहीं लड़कियां भी फौज में हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल डी. पी. सिंह जिन्हें पदोन्नति मिली तो उन्हें मैडल उनकी दोनों बेटियों ने पहनाए जो कि आर्मी में ही मेजर के पद पर तैनात थीं। एक बाप के लिए यह गौरवांवित पल रहे होंगे कि उसकी बेटियां भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए देश की रक्षा में तत्पर हैं। मगर अफसोस तब होता है जब विदेशों में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे वह लोग जिनकी गिनती ना के बराबर है जो सिखी स्वरूप में भी नहीं मगर अपने आप को सिख कहते हैं और खालिस्तान की बातें करते हैं। पाकिस्तान की शह पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उनकी वजह से समूची सिख कौम बदनाम होने लगती है दिलजीत फिल्म "सरदार जी 3" में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर आलोचना झेल रहे हैं। तमाम भारतीय सितारों, गायकों और फिल्म संगठनों ने उनका विरोध किया है। हालांकि देखा जाए तो फिल्म में अभिनेत्री उन्हें दिलजीत ने नहीं बल्कि फिल्म के निर्माता ने लिया होगा। उसने पहलगांव हादसे के बाद जिस प्रकार भारत के खिलाफ जहर उगला उसके चलते उसकी आलोचना बनती भी है मगर जो लोग दिलजीत को गद्दार या उसके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिलजीत ने हमेशा ही अपने देश और कौम का गौरव बढ़ाया है। विश्व की सबसे महंगी मैग्जीन के मुख्य पृष्ठ पर आज अगर किसी भारतीय की तस्वीर छपी है तो वह दिलजीत दोसांझ है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो.: 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/30882)

नई दिल्ली (इंद्रजीत सिंह) वार्ड नं0 43 सुल्तानपुरी में डेंगू डे समारोह मनाया गया जिस में मुख्य अतिथि मान्य प्रेम कुमार मंडल , उपायुक्त, रोहिणी जोन डॉ अजय कुमार , जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ हरलिन कौर, निगम पार्षद,बॉबी राजपाल वे सचिन दहिया व नरेश वलिया RWA , NGO ,market associate, सुल्तानपुर माजरा रेसीडेंस वेल्फेयर Association मेंबर वह वार्ड के अन्य सदस्यों तथा MCD के सभी कर्मचारी के सहयोग से डेंगू डे समारोह संपन्न हुआ .

सांसद और अधिकारियों ने विकास योजनाओं की समीक्षा, जनहित में ठोस कार्रवाई का संकल्प

देवरिया।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता और सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर जनपद की विकास योजनाओं, उनकी प्रगति और जनकल्याण से जुड़ी प्राथमिकताओं पर गहन समीक्षा की। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि जिले का विकास तभी संभव है जब अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष फोकस करते हुए कार्यों में गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। वहीं सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन, प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चिन्हित समस्याओं और जरूरतमंद लाभार्थियों का सर्वे ईमानदारी से हो, यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चिकित्सकों की तैनाती और कटान रोकने के लिए जरूरी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की। बैठक में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर कुशवाहा, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद और बरहज विधायक दीपक मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं पर प्रकाश डाला। बेसिक विद्यालयों के समायोजन, जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति, स्कूलों की चारदीवारी, सड़क मरम्मत, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना जैसे मसलों पर गंभीर चर्चा हुई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बैठक में दिए गए सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिशा समिति के निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ा कोई भी मामला आगामी बैठकों में लंबित न रहे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए संचालित योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, सीएमओ डॉ. अनिल गुप्ता, बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक डीआरडीए, मनरेगा उपायुक्त, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जनपद में उर्वरक भरपूर मात्रा में उपलब्धता- कृषि अधिकारी

कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ0 मेनका ने बताया कि वर्तमान समय में खरीफ की फसलों में धान की बुवाई / गन्ने की टाप ड्रेसिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जनपद में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता बनी हुई है। जनपद में अभी यूरिया 14674 मी0टन, डी0ए0पी0 2479.00 मी0टन, एन0पी0के0 4282.00 विभिन्न उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है। सहकारिता क्षेत्र में प्रिपोजिसनिंग से 880.00 मी0टन यूरिया जनपद की 88 समितियों को आवंटित कर दिया गया है, जिसे एक से दो दिन में समितियों को प्रेषित कर दिया जायेगा। साथ ही इफको की 1200.00 मी0 टन डी0ए0पी0 एवं 1300.00 मी0टन यूरिया इसी सप्ताह देवरिया रैक प्राप्त हो रही है, जिसे समितियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उन्होंने किसान बंधुओं से अनुरोध किया है कि संस्तुत मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। विभागीय पोर्टल पर

सहकारीता क्षेत्र में प्रिपोजिसनिंग से 880.00 मी0टन यूरिया जनपद की 88 समितियों को आवंटित कर दिया गया है, जिसे एक से दो दिन में समितियों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने किसान भाईयों से अपील किया है कि अपनी आवश्यकतानुसार जोत बही/खतौनी के अनुसार अपने नजदीकी निजी / सहकारी क्षेत्र के उर्वरक प्रतिष्ठान से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से आधार कार्ड से उर्वरक प्राप्त करें। साथ ही किसान भाईयों से यह भी अपील की जाती है कि उर्वरक क्रय करने में किसी प्रकार की समस्या हेतु कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 8317015135 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। जिसका निस्तारण तत्कालिक रूप से किया जायेगा।

सावन माह को लेकर मंडलायुक्त व डीआईजी सतर्क, तैयारियों की हुई उच्चस्तरीय समीक्षा

देवरिया।

आगामी सावन माह में जनसुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन सुनिश्चित करने हेतु गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और पुलिस उप महानिरीक्षक शिवासिम्पी चिनप्पा ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों संग बैठक कर शांति व सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ढींगरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रियों व शिवभक्तों की सुरक्षा और सहूलियत सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने नदियों व घाटों पर बैरिकेटिंग, सुरक्षा बलों की तैनाती, और चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ अस्थायी विश्राम स्थलों, पेयजल व सफाई व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण, जाम प्रबंधन, और संवेदनशील स्थानों की निगरानी को लेकर सभी विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करना होगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रमुख स्थलों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। डीआईजी शिवासिम्पी चिनप्पा ने बैठक में कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने सभी थानों में नियमित गश्त, संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग और खुफिया इकाई की सक्रियता पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने मंडल स्तरीय अधिकारियों को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा रही है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर श्रुति शर्मा, एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

श्रीमद्भागवत कथा में गूंजे जय श्रीकृष्ण के जयकारे

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र के मिश्रौली दीक्षित गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला।

कथावाचक पंडित वागीश मणि त्रिपाठी ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का संगीतमय वर्णन कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

कथा के दौरान पूतना वध, शकटासुर मर्दन, यमलार्जुन उद्धार, कालिया नाग दमन, माखन चोरी और गोपियों संग रास जैसे प्रसंगों को हृदयस्पर्शी अंदाज में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। बाल्यकाल से ही उन्होंने यह संदेश

वागीश जी ने बाल लीलाओं से किया भावविभोर

दिया कि धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का कर्तव्य है। पं. वागीश ने अपने प्रवचन में कहा कि आज के समय में यदि हम समाज को दिशा देना चाहते है, तो हमें अपने घरों में बच्चों को संस्कार देना होगा। धार्मिक आयोजन, शास्त्रों का श्रवण और सच्चा आचरण ही समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। कथा में आस-पास के गांवों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा स्थल पर भजन-कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें भक्तों ने राधे-राधे और जय श्रीकृष्ण के जयघोष के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर यजमान विनोद दीक्षित, अश्वनी राय, ज्ञान प्रकाश तिवारी, सुमन्त दीक्षित, विजय नारायण दीक्षित, हृदयानारायण, हरिशंकर दीक्षित, भगवती यादव, राम नगीना दीक्षित सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

रचनात्मक पेशेवरों ने सीखी शॉर्ट फिल्म निर्माण की बारीकियां

देवरिया। पूर्वांचल में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की दिशा में गुरुवार को जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल ने नई पहल की। देवरिया के बरपार स्थित बरगद सभागार में शॉर्ट फिल्म निर्माण और स्टोरीटेलिंग पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, मऊ, बलिया सहित विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों और रचनात्मक पेशेवरों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कुणाल चोपड़ा ने प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण की प्रारंभिक बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हर इंसान अपने आप में एक्टर, क्रिएटर और डिजाइनर है, लेकिन अब तक इसके लिए अवसर बड़े शहरों तक ही सीमित थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह मंच ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया है।

अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, लेखपाल से मारपीट और जानलेवा हमले के प्रयास में तीन आरोपी गिरफ्तार

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के मिठहा माफी गांव में बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम पर अराजक तत्वों द्वारा किए गए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना उस समय हुई जब हल्का लेखपाल अनन्त सिंह, उपजिलाधिकारी के निर्देश पर चकरोड से अतिक्रमण हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे थे।जानकारी के अनुसार गांव के सार्वजनिक चकरोड पर कुछ लोगों द्वारा गन्ने के सूखे पत्ते व अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा था। ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।जब राजस्व टीम अतिक्रमण हटवा रही थी, तभी अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते लेखपाल से वाद-विवाद, धक्का-मुक्की और मारपीट पर उतर आए।

यही नहीं, सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए गए और एक आरोपी ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर एक्ट के तीन अपराधियों को मिली सश्रम कारावास की सज़ा

देवरिया। जनपद पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन‌ के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक दशक पुराने प्रकरण में पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते तीन शातिर अपराधियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

युवती की संदिग्ध परिस्थितियोंमें हुई मौत

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौका टोला गांव में एकयुवती की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। घटना बुधवार शाम को 6:47 मिनट पर ही परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी को सूचना दिए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में न तो ग्रामीणों ने और न ही मृतका के परिजनोंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई। गांव में युवतीकी मौत को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रहीहै। हालांकि, अभी तक मौत का सही कारण सामने नहींआ पाया है।थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि उन्हें घटना की कोईजानकारी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है, तो मामले की जांच करआवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना की पुष्टि न होने के कारण पुलिस कोई बयान नहीं दे रही है।

कांग्रेस पार्टी जिला इकाई कुशीनगर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

पडरौना,कुशीनगर। जिला कांग्रेस कमेटी कुशीनगर के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित जिला पंचायत के सभागार में संपन्न हुआ। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र राधे विश्वकर्मा ने की मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो रहे जबकि विशिष्ट अतिथि आलोक मल्ल की उपस्थिति रही संचालन जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मोहम्मद वारिस उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह मोहम्मद जहीरुद्दीन आफताब आलम स्वामीनाथ यादव प्रभु गुप्ता आकाश सिंह शाहनवाज खातून रंजीत प्रसाद अभय चौबे महामंत्री लालबाबू मीडिया प्रभारी अरविंद खरवार सहित अन्य पदाधिकारी ने शपथ लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनंजय सिंह पहलवान नागेंद्र सिंह स्वामीनाथ यादव राज कपूर राय आदि लोगों ने भी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जागरूकता ने बदली सोंच, हुआ बच्चों का टीकाकरण

पडरौना,कुशीनगर। किदवई नगर छावनी में रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण हुआ। इस जगह पर ऐसे सात परिवार जिन्होंने टीकाकरण के लिए इंकार किया था उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम तथा रेडियो प्रज्ञा की टीम की जागरूकता ने अपने बच्चों का टीकाकरण करने के लिए राजी कर लिया। आशा कार्यकर्ता वाहिदा परवीन ने घर-घर भ्रमण करने के दौरान यह जानकारी दी की कई लोग गलतफहमियों के शिकार है और टीकाकरण नहीं करवाने के लिए कह रहे हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार यादव डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सोनी और यूनिसेफ से शाहनवाज, मिनहाज,रेडियो प्रज्ञा से तेज नारायण श्रीवास्तव, नवनीत और साइना के साथ ही चिकित्सा की टीम में डॉक्टर उमर जमई,डॉक्टर गुरु प्रसाद व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में विनोद शाह सुमित श्रीवास्तव प्रमोद कुमार बीएमसी रेनु मॉनिटर अनुभव मिश्रा तारिक अली जफर आदि की तत्परता से सात परिवार के लोगों ने अपने बच्चों का टीकाकरण कराया। लोगों ने रेडियो प्रज्ञा के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई की भी प्रशंसा की।

गांव के मुख्य मार्ग पर जल भराव से परेशान ग्रामीणों नें रोपा धान

तमकुही राज,कुशीनगर । तमकुही विकास खंड क्षेत्र के गांव बसडीला महंथ के मुख्य मार्ग पर जल निकासी के अभाव में आये दिन हो रहे जल जमाव से आजिज हुए ग्रामीणों ने गुरुवार को उस मार्ग पर धान की रोपनी कर अपनी आक्रोश को प्रदर्शित किया और प्रशासन से मांग किया कि तत्काल मुख्य मार्ग से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उक्त गांव के मुख्य मार्ग पर थोड़ा भी बरसात होने पर गांव की पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है। ग्रामीणों को कहना है कि मुख्य मार्ग के दोनों ओर लोग अपने दरवाजे व द्वार पर मिट्टी की भराई कर ऊंचा कर लिये है। जिससे पानी की निकास बंद है। मुख्य मार्ग गांव के अन्य जगहों से खाल होने से पूरे गांव का पानी इसी जगह आकर इकट्ठा हो जा रहा है। जबकि कई बार प्रधान से भी इस मार्ग को ठीक कराने का अनुरोध ग्रामीण कर चुके है। लेकिन बजट के अभाव बताकर प्रधान द्वारा उक्त मार्ग को ठीक नही कराया गया। जिससे गांव के लोगों को इस गंदा पानी को लांघ कर ही अपने गंतव्य की ओर जाना और आना पड़ता है। वहीं विद्यालय जाने वाले बच्चों का ड्रेस आने जाने वाले वाहन व बाइक के छींटे से प्रतिदिन खराब हो जा रहा है या बच्चे जिसमें फिसल कर गिर जा रहे है।गुरूवार के गांव विनय गौतम,विशाल मद्देशिया, संजीव यादव, अशोक मद्देशिया, मंटू कुमार,शिवजी,बिहारी प्रसाद आदि ने आक्रोश व्यक्त करते हुये उक्त सड़क पर लगें पानी मे धान की रोपनी कर अपनी विरोध प्रगट किया। इनका कहना था कि उनके बार बार अनुरोध के बाद भी प्रधान व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इनके इस दुर्दशा को संज्ञान अबतक नहीं लिया है। इस लिये वह विरोध में सड़क पर धान की रोपनी कर रहे है।प्रधान राजीव कुमार गौतम का कहना है कि सड़क लोकनिर्माण द्वारा बनवाया गया है। अगल बगल के लोगों द्वारा जल निकासी को बंद किया गया है। वह क्षेत्रीय लेखपाल को बुलाये है कि बंद जल निकासी को खुलवाया जाएं ताकि जल भराव की समस्या खत्म हो जाये।

कांग्रेस की नव गठित कमेटी में इस्तीफों का सिलसिला जारी

बहराइच। गत दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी की गई बहराइच की जिला कार्यकारिणी पर विरोध का स्वर उग्र होता जा रहा है। 74 में से 17 लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और आज जिला सचिव पद से लाल बहादुर तिवारी एवं जगदीश सिंह ने त्याग पत्र दे दिया। मालूम हो कि जिला महासचिव सुषमा त्रिपाठी, जिला सचिव पद से एडवोकेट होरी लाल राव, महताब आलम, सोनम सैनी, मंजू सैनी, शालिनी सैनी, हनुमान प्रसाद आर्य, इकबाल अहमद सलमानी, सुशील उपाध्याय, पूनम मिश्रा, एहसान वारिस, डॉ राधेश्याम गुप्ता, जिला सचिव पद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम सुंदर तिवारी, जिला महासचिव पद से दीना नाथ पाण्डेय, जिला सचिव पद से डॉ हनुमान प्रसाद, राजेश मिश्र, नबी अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। अब 74 में से 19 लोगों का त्यागपत्र हो चुका है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिला कमेटी में फर्जीवाड़ा करके बनाया गया है। इस कमेटी में न तो जातिगत समीकरण बैठाया गया है न वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया गया है। उपाध्यक्ष और महासचिव पद को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के खिलाफ यह कमेटी जारी होने के बाद विरोध और लामबंद होता जा रहा है।

अप्रैल-जून तिमाही में विदेशी फंड प्रवाह घटा, रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 33 प्रतिशत लुढ़का

नई दिल्ली । वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते अप्रैल-जून 2025 के दौरान भारत में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश में गिरावट आई है। इसका मतलब है कि देश में रियल एस्टेट सेक्टर (जैसे मॉल, ऑफिस, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आदि) में बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाने वाला निवेश पहले की तुलना में कम हो गया है। रियल एस्टेट परामर्शदाता कॉलियर्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून 2025 में संस्थागत निवेश 33 प्रतिशत घटकर 1.69 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 2.53 अरब था। इस गिरावट की मुख्य वजह विदेशी फंडिंग में लगभग 50 प्रतिशत की कमी रही, जो 2,046.8 मिलियन डॉलर से घटकर 1,048.4 मिलियन डॉलर रह गई। हालांकि, घरेलू निवेशकों ने बाजार में भरोसा जताया और अप्रैल-जून तिमाही में 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 642.8 मिलियन डॉलर का निवेश किया। यह पिछले साल की समान अवधि में 486.5 मिलियन डॉलर था। कॉलियर्स इंडिया के सीईओ, बादल यादिक ने कहा कि घरेलू पूंजी अब भारत के रियल एस्टेट निवेश में एक प्रमुख चालक बनकर उभरी है। 2021 में कुल निवेश में इसकी हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी। यह 2024 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद 2025 की पहली छमाही में घरेलू निवेश का हिस्सा कुल निवेश का 48 प्रतिशत रहा। इससे कुल निवेश 3 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच सका। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-जून 2025 के दौरान कुल संस्थागत निवेश 15 प्रतिशत घटकर 2,998.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह एक साल पहले इसी अवधि में 3,528.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस दौरान विदेशी निवेश 1,570.6 मिलियन डॉलर रहा, जो पिछले साल के 2,593.8 मिलियन डॉलर से काफी कम है। वैश्विक निवेशक उभरते व्यापक आर्थिक परिदृश्यों, ऋण प्रवाह और महंगाई के दबावों के बीच सतर्क बने हुए हैं। इसके विपरीत, घरेलू निवेशकों ने 1,427.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जो कि 2024 की पहली छमाही के 934.7 मिलियन डॉलर की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संस्थागत निवेश में फंडिंग के स्रोतों में फैमिली ऑफिसेज, विदेशी कंपनियां, विदेशी बैंक, पेंशन फंड्स, निजी इक्विटी, रियल एस्टेट डेवलपर्स फंड, विदेशी एनबीएफसी, सूचीबद्ध रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और संप्रभु संपत्ति कोष शामिल हैं।

एक नजर

पतंजलि को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन चलाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डाबर की याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश विशेष रूप से डाबर च्यवनप्राश और सामान्य रूप से च्यवनप्राश का अपमान कर रहा है। पतंजलि के विज्ञापन में दावा किया गया है कि किसी अन्य निर्माता को च्यवनप्राश तैयार करने का ज्ञान नहीं है- जो सामान्य अपमान है। याचिका में दावा किया गया है, इसके अलावा, विज्ञापनों में (आयुर्वेदिक औषधि/दवा के संबंध में) गलत और भ्रामक बयान दिए गए हैं। इसमें डाबर च्यवनप्राश के साथ अपमानजनक तुलना की गई है। डाबर की ओर से अधिवक्ता जवाहर लाला और मेघना कुमार उपस्थित हुए। याचिका में आगे दावा किया गया कि विज्ञापन में अन्य सभी च्यवनप्राश के संबंध में साधारण उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो दर्शाता है कि वे निम्न हैं। विज्ञापन में यह भी गलत दावा किया गया कि अन्य सभी निर्माताओं को आयुर्वेदिक ग्रंथों और च्यवनप्राश तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए फार्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय की है।

महाराष्ट्र व यूपी के बाद अब गुजरात ने भी पार किया एक करोड़ निवेशकों का आंकड़ा

नई दिल्ली । भारत में शेयर बाजारों से जुड़ने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुजरात अब पंजीकृत निवेशकों में एक करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। निफ्टी ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात ने इस आंकड़े को पार किया है। इन तीन राज्यों का देश के कुल निवेशक आधार में 36 प्रतिशत योगदान है। यह भारत की बढ़ती इक्विटी भागीदारी को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। मई 2025 तक एनएसई के आंकड़ों से पता चला कि भारत में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या 11.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अकेले मई महीने में 11 लाख से अधिक नए निवेशक जुड़े। यह 9 प्रतिशत की मासिक वृद्धि को दर्शाता है, जो नए पंजीकरण में लगातार चार महीनों की गिरावट के बाद मजबूत उछाल का संकेत है। क्षेत्रवार बात करें तो उत्तर भारत 4.2 करोड़ पंजीकृत निवेशकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि पश्चिम भारत में 3.5 करोड़ निवेशक हैं। दक्षिण भारत में 2.4 करोड़ निवेशक हैं, जबकि पूर्वी भारत में 1.4 करोड़ निवेशक हैं। पिछले 12 महीनों में उत्तर और पूर्वी भारत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। उत्तर भारत में 24 प्रतिशत और पूर्वी भारत में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं दक्षिण भारत में 22 प्रतिशत और पश्चिम भारत में 17 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। कुल मिलाकर विकास पैटर्न में वृद्धि हुई है। फरवरी 2024 में 9 करोड़ निवेशकों के आंकड़े तक पहुंचने के बाद, हर पांच से छह महीने में एक करोड़ निवेशक जुड़े। अगस्त 2024 तक आंकड़ा 10 करोड़ पहुंच गया और जनवरी 2025 तक 11 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि, फरवरी से मई 2025 तक के बाद के महीनों में विकास दर काफी धीमी हो गई। इसके बाद हर महीने औसतन 10.8 लाख नए निवेशक जुड़े। कैलेंडर वर्ष 2025 में देखे गए 19.3 लाख नए निवेशक जुड़ने के मासिक औसत की तुलना में इसमें काफी गिरावट आई। मंदी के बावजूद मई में हुई हालिया तेजी निवेशकों की नई रुचि का संकेत है। यह भारतीय पूंजी बाजारों में खुदरा भागीदारी के विस्तार को भी उजागर करती है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर नए कारोबार में तेजी के कारण जून में 10 महीने के उच्च स्तर पर, पीएमआई से पुष्टि

नई दिल्ली । मांग के सकारात्मक रुझान और बिक्री में जारी सुधार के बीच अंतरराष्ट्रीय बिक्री और रोजगार सृजन में मजबूत विस्तार होने से जून में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

एक मासिक सर्वेक्षण में गुरुवार को इसकी पुष्टि की गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मई में 58.8 से बढ़कर जून में 60.4 हो गया, जो नए व्यावसायिक ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में, 50 से ऊपर का अंक विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता है। एचएसबीसी के मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, सेवा पीएमआई व्यवसाय गतिविधि सूचकांक दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण नए घरेलू ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि थी। नए निर्यात ऑर्डरों में भी वृद्धि हुई, यद्यपि धीमी गति से। मार्जिन में सुधार हुआ, क्योंकि इनपुट लागत में वृद्धि आउटपुट शुल्कों के मुकाबले कम थी। आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 के बाद से नए ऑर्डरों में सबसे तेज वृद्धि हुई। सेवा कंपनियों को घरेलू बाजार की निरंतर मजबूती से सबसे अधिक लाभ हुआ। साथ ही नए निर्यात कारोबार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पैनल के सदस्यों के अनुसार, विदेशी मांग में विशेष रूप से एशियाई, मध्य पूर्वी और अमेरिकी बाजारों से सुधार हुआ है। भारतीय सेवा क्षेत्र के निरंतर विस्तार का भर्ती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जून में लगातार 37वें महीने रोजगार में वृद्धि हुई। मई के रिकॉर्ड से धीमी होने के बावजूद रोजगार वृद्धि की दर अपने दीर्घकालिक औसत से आगे निकल गई। सर्वेक्षण में कहा गया है कि मूल्य के मोर्चे पर, लागत दबाव उपभोक्ता सेवा श्रेणी में सबसे अधिक था, जबकि आउटपुट शुल्क में सबसे तेज वृद्धि वित्त और बीमा क्षेत्र में देखी गई। सर्वेक्षण के अनुसार, एक वर्ष के समय में उत्पादन स्तर के दृष्टिकोण के बारे में आशावाद कायम रहा, 18 प्रतिशत सेवा प्रदाताओं ने वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। हालांकि, उत्साहित फर्मों का यह अनुपात 2022 के मध्य के बाद से सबसे कम था। इसलिए, आत्मविश्वास का समग्र स्तर गिर गया और अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे था।

अमीरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर : इस शख्स बेजोस को पछाड़ा, जुकरबर्ग की पोजिशन पर भी मंडराया खतरा

बिजनेस डेस्क। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। Oracle के को-फाउंडर लैरी एलिसन अब तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। यह बदलाव ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स में बुधवार को हुए नेटवर्थ के उतार-चढ़ाव के बाद दर्ज किया गया। एलिसन की नेटवर्थ में 10.3 अरब डॉलर की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी कुल संपत्ति 246 अरब डॉलर तक पहुंच गई। साल 2025 में अब तक उनकी संपत्ति में 54.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर, जेफ बेजोस की संपत्ति में 67.2 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उनकी नेटवर्थ घटकर 241 अरब डॉलर रह गई और वे चौथे स्थान पर चले गए। एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, की नेटवर्थ में बुधवार को 10.7 अरब डॉलर की बढ़त दर्ज की गई। टेस्ला के शेयरों में 4.97% की तेजी इसका प्रमुख कारण रही। हालांकि इससे एक दिन पहले ही उनकी संपत्ति में 12 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट हुई थी। मस्क की कुल संपत्ति अब 361 अरब डॉलर है लेकिन इस साल अब तक उनकी नेटवर्थ में 71.2 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है, जो इस वर्ष सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। मेटा (फेसबुक) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 252 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। एलिसन से अब सिर्फ 6 अरब डॉलर का अंतर रह गया है, जिससे आने वाले दिनों में रैंकिंग में और बदलाव की संभावना है। मुकेश अंबानी 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं, जबकि गौतम अडानी 85.2 अरब डॉलर के साथ 20वें स्थान पर बने हुए हैं। एशिया में अंबानी अभी भी सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।

यूएस-वियतनाम व्यापार समझौते से सबक ले सकता है भारत, जीटीआरआई की रिपोर्ट में अहम संकेत

वॉशिंगटन । हाल ही में अमेरिका और वियतनाम के बीच व्यापार समझौता हुआ है। इस व्यापार समझौते से भारत कई सबक सीख सकता है। खासकर भारतीय निर्यातकों पर इसका गहरा असर हो सकता है। भारत, वियतनाम को निर्यात के मामले में प्रतिद्वंद्वी और क्षेत्रीय सहयोगी दोनों मानता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट में यह बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और वियतनाम में जब साल 2000 में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद वियतनाम के उत्पाद अमेरिका में सिर्फ 2 से 10 प्रतिशत टैरिफ पर आने लगे। अब ट्रंप प्रशासन ने नई डील में वियतनामी उत्पादों के अमेरिका में आने पर 20 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम से वियतनाम का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। जीटीआरआई ने कहा कि भारतीय निर्यातकों को भी इससे सबक लेना चाहिए। साल 2000 में हुए व्यापार समझौते के बाद वियतनाम के उत्पादों की अमेरिका में आवक काफी बढ़ गई और एक समय जो वियतनाम का निर्यात सिर्फ 80 करोड़ डॉलर था, वह बढ़कर 135 अरब डॉलर हो गया। विशेषज्ञों का दावा है कि नए टैरिफ के बाद वियतनाम की यह बढ़त खत्म हो सकती है और इससे वियतनाम का निर्यात सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित होगा। इतना ही नहीं वियतनाम होकर अमेरिका आने वाले चीनी सामान पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का यह कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। जीटीआरआई ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। ऐसे में भारत की तरफ से बातचीत कर रहे लोगों को सलाह है कि वे वियतनाम के अनुभव से सीखें और पुरानी छूट को वापस लेने, टैरिफ लगाने और सामान के उत्पादन की जगह को लेकर अस्पष्ट नियमों पर अमेरिका के साथ स्पष्ट बातचीत करें।

हरे निशान पर हुई घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत; सेंसेक्स ने पकड़ी रफ्तार, निफ्टी ने भी लगाई छलांग

नई दिल्ली । भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के बीच एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख को दर्शाते हुए गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका-वियतनाम व्यापार समझौते का भी घरेलू शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 242.83 अंक चढ़कर 83,652.52 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 83.65 अंक चढ़कर 25,537.05 अंक पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वियतनाम के टैरिफ को 46 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के लिए एक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि भारत की प्रभावी टैरिफ दर 15-18 प्रतिशत के आसपास हो सकती है। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, बाजार निफ्टी को 26,277.35 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, सभी की निगाहें गुरुवार को आने वाले जून के अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल आंकड़ों पर है - कमजोर आंकड़े फेड की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जबकि मजबूत आंकड़े उन्हें कम कर सकते हैं। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटरनल और टाटा मोटर्स सर्वाधिक लाभ में रहीं। हालांकि, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व पिछड़ गए। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट पर था। बुधवार को अमेरिकी बाजार अधिकतर बढ़त के साथ बंद हुए। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, निफ्टी के कुछ समय तक 25,200-25,800 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जब तक कि कोई ट्रिगर इस दायरे को तोड़ नहीं देता। कुछ दिनों में घोषित होने वाले संभावित भारत-अमेरिका व्यापार सौदे से सकारात्मक ट्रिगर मिल सकता है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.77 प्रतिशत घटकर 68.58 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,561.62 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी बेची। पिछले सत्र में बीएसई सेंसेक्स 287.60 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,409.69 पर बंद हुआ था। निफ्टी 88.40 अंक या 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,453.40 पर बंद हुआ।

सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी, चांदी में आई गिरावट

बिजनेस डेस्क। गुरुवार (3 जुलाई) को सोने की कीमतों में तेजी जारी

है और चांदी में गिरावट। खबर लिखे जाने के समय सोने का भाव 0.05 फीसदी की तेजी के साथ 97,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं चांदी 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 1,07,452 रुपए प्रति किग्रा पर है। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें बुधवार को 500 रुपए बढ़कर 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गईं। अमेरिकी शुल्क को लेकर नयी चिंताओं के बीच भारी वैश्विक खरीद होने से सोने में यह तेजी देखी गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले सत्र में मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,200 रुपए बढ़कर 98,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। दो लगातार सत्रों में सोने में 1,700 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 450 रुपए बढ़कर 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। पिछले कारोबार में यह 98,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

पीपीएफ में निवेश से बन सकता है करोड़ों का फंड, बस करना होगा ये काम

बिजनेस डेस्क । केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर को 7.1 फीसदी सालाना पर स्थिर बनाए रखा है। यह स्कीम भारत में खासकर सैलरीड क्लास और सुरक्षित निवेश चाहने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है। लंबी अवधि में टैक्स फ्री रिटर्न और बिना जोखिम के बड़ा फंड तैयार करने की सुविधा के चलते यह योजना हर नौकरीपेशा के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 28 साल की उम्र में पीपीएफ अकाउंट खोलता है और 58 साल की उम्र तक यानी 30 साल तक हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है, तो उसे कुल 45 लाख का निवेश करना होता है। सरकार द्वारा तय 7.1 फीसदी ब्याज दर के मुताबिक 30 साल बाद यह फंड बढ़कर करीब 1.54 करोड़ रुपए हो जाता है। इसमें

से लगभग 1.09 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में मिलते हैं और सबसे खास बात, यह पूरी राशि टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है लेकिन इसे हर बार 5-5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरह 30 साल की नौकरी के दौरान तीन बार एक्सटेंशन लेकर निवेश जारी रखा जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद भी यदि आप निवेश बंद कर दें, तो भी अकाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है और उस पर मिलने वाला ब्याज जारी रहता है। इस दौरान आप हर साल उस ब्याज को निकाल भी सकते हैं यानी एक तरह से टैक्स फ्री पेंशन जैसी इनकम मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर 30 साल में पीपीएफ अकाउंट का फंड 1.50 करोड़ रुपए हो जाता है, तो उस पर 7.1 फीसदी सालाना के हिसाब से 10.65 लाख ब्याज बनता है। इसे 12 महीने में बांटा जाए तो करीब 88,750 प्रति माह की टैक्स फ्री इनकम मिलती है - वो भी बिना किसी बाजार जोखिम के। विशेषज्ञों के अनुसार, पीपीएफ एक ऐसा सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प है जिसे हर नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनाना चाहिए। समय पर निवेश की शुरुआत और सही तरीके से एक्सटेंशन लेने से यह योजना आपको बिना किसी जोखिम के करोड़पति बना सकती है।

यूएस-वियतनाम ट्रेड डील से एक्सपर्ट हैरान, कहा- अब तो भारत को होना ही पड़ेगा सावधान

नई दिल्ली । अमेरिका और वियतनाम के बीच नई ट्रेड डील ने जहां एक तरफ भारत की चिंता बढ़ाकर रख दी है तो वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ी सीख भी है, खासकर उन निर्यातकों के लिए जो वियतनाम को भी एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी देश मानता है. ये बात ग्लोबल ट्रेड रिसर्च यानी जीटीआरआई ने अपने रिपोर्ट में कही है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 में यूएस-वियतनाम के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते हुए थे. इसमें अमेरिका में वियतनाम के सामानों की एंट्री पर 2 से 10 प्रतिशत रियायत टैरिफ लगाने पर सहमते हुए थे. लेकिन उसके बावजूद इस नई डील में अब वियतनाम से आने वाले सभी सामानों की अमेरिका में एंट्री पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इस डील का सीधा असर वियतनाम से होने वाले 135 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर पड़ना तय है, जिसने दो दशक के उदारवादी ट्रेड नीति को पलट कर रख दिया है. जीटीआरआई का कहना है कि भारतीय एक्सपोर्टर वियतनाम को अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं. ऐसे में इस डील से जहां एक तरफ भारत को सीख लेने की जरूरत है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी रणनीति भी देखने की जरूरत है. इस नई डील में अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद को वियतनाम में सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है. हालांकि, अमेरिका ने वियतनाम से आने वाले सामानों पर टैरिफ की दरें काफी ऊंची रखी है. पहले से प्रस्तावित टैरिफ 46 प्रतिशत में तोकमी की गई है, लेकिन साल 2000 में जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था, उसके मुकाबले दोगुना या फिर तीन गुने ज्यादा टैरिफ लगाया गया है. साल 2001 से ही अमेरिकी बाजार में वियतनाम के सामान जैसे कपड़े, जूते-चप्पल, समुद्री मछली, हाथ से बना उत्पाद और कृषि उत्पादों के निर्यात को कम टैरिफ की वजह से फायदा मिला. इसके बाद अमेरिकी बाजार में वियतनाम के सामानों का 800 मिलियन डॉलर से निर्यात बढ़कर 135 बिलियन डॉलर हो गया. ऐसे में वियतनाम के सामानों पर 20 प्रतिशत नई नई टैरिफ दरों के लगने से उसे अब पहले जैसे फायदे नहीं मिल पाएंगे. साथ ही, अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा भी कमजोर पड़ जाएगी.

दो महीने पहले 6000 स्टाफ की छंटनी, अब 9000 को सड़क पर लाएगी ये दिग्गज टेक कंपनी

नई दिल्ली । तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 2 साल में दूसरी बड़ी छंटनी करने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने कुल स्टाफ के करीब 4 प्रतिशत के ऊपर अब कैंची चलाने जा रही है, जिससे 9000 से ज्यादा कर्मचारी अब सड़क पर आ जाएंगे. सिएटल टाइम्स में ये खबर सामने आयी है. साल 2023 के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी छंटनी है. ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के निकाले जाने के पीछे खर्चे को कम करना और आर्थिक तौर पर अनिश्चितता है. 2024 के जून में कंपनी में कुल 22800 कर्मचारी काम कर रहे थे. जून में ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि टेक कंपनी हजारों स्टाफ को बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है, खासकर सेल्स में लगे लोगों की. इस साल मई के महीने में माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 6000 लोगों को बाहर निकाला था. तो वहीं जून के महीने में 300 स्टाफ को बाहर किया था. अब फिर से करने जा रही दो साल में इस सबसे बड़ी छंटनी को लेकर अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.